

बिहार की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और सरकारी खर्च के बीच संबंध

डॉ अमरकांत चौधरी

सहायक प्राध्यापक, सीनियर स्केल, अर्थशास्त्र विभाग,
जे. एम. डी. पी. एल महिला कॉलेज,
मधुबनी बिहार, एल. एन. एम. यू. दरभंगा.

सार

अर्थनीति के सन्दर्भ में, सरकार के राजस्व संग्रह (करारोपण) तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति (fiscal policy) कहलाता है। अतः राजकोषीय नीति के दो मुख्य औजार हैं – कर स्तर एवं ढांचे में परिवर्तन तथा विभिन्न मदों में सरकार द्वारा व्यय में परिवर्तन। यह अध्ययन भारत में मुद्रास्फीति और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के बीच संबंधों की जांच करना चाहता है। भारतीय रिजर्व बैंक से एकत्र किए गए वार्षिक डेटा का उपयोग करके संयोग और त्रुटि सुधार मॉडल से एक अनुभवजन्य साक्ष्य प्राप्त किया जाता है। बिहार के वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 22 फरवरी, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया। कोविड-19 के असर की वजह से वर्ष 2020–21 अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त के लिहाज से स्टैंडर्ड वर्ष नहीं था।

कुंजीशब्द: मुद्रास्फीति, सरकार

प्रस्तावना

ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति के बिना चल सकती हो। पर बहस इस बात की है कि आर्थिक प्रबंधन के लिए दोनों में कौन सी नीति की भूमिका मुख्य होनी चाहिए। सरकारी निर्माण परियोजनाओं, जम कर टैक्स लगाने और आर्थिक जीवन में अन्य हस्तक्षेपों के ज़रिये माँग और रोज़गार बढ़ाने के पक्षधर राजकोषीय नीतियों के विवेकसम्मत इस्तेमाल को आर्थिक वृद्धि की चालक शक्ति मानते हैं। घाटे की अर्थव्यवस्था को यह विचार मुख्यतः कींसियन अर्थशास्त्र की देन है। यह रवैया राजकोषीय नीतियों को प्रमुखता प्रदान करता है। कींसियन अर्थशास्त्र का बोलबाला होने से पहले मौद्रिक नीति के ज़रिये आर्थिक प्रबंधन करने का चलन था। साठ के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएँ एक बार फिर मौद्रिक नीति को मुख्य उपकरण बनाने की तरफ़ झुकीं। उन्होंने कींसियन दृष्टिकोण की आलोचना की। मौद्रिक नीति के समर्थकों की मान्यता है कि टैक्स कम लगाने चाहिए और मौद्रिक नीति को सरकार के विवेक के भरोसे छोड़ने के बजाय कुछ निश्चित नियम-कानूनों के तहत चलाया जाना चाहिए। केवल इसी तरह से अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबंधन हो सकता है और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखा जा सकता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इस विचार को मौद्रिकवाद या मोनेटरिज़म की संज्ञा दी जाती है।

मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक (जैसे भारत का रिज़र्व बैंक) द्वारा किया जाता है। यह बैंक तयशुदा समष्टिगत आर्थिक नीतियों के तहत सरकार के कहने पर भी कदम उठाता है और सरकार से स्वतंत्र निर्णय भी लेता है। शुरू में मौद्रिक नीति आम तौर पर केवल ब्याज दरों में परिवर्तन और खुले बाज़ार के कामकाज के आधार पर ही चलती थी। बाद में मुद्रा बाज़ार का अनुभव और अन्य मौद्रिक उपकरणों के विकास के बाद मौद्रिक नीति का संचालन उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चला गया। अमेरिका में गवर्नरों के फ़ेडरल रिज़र्व बोर्ड ने 1913 से ही आरक्षित मुद्रा की आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था में सकल मुद्रा की वृद्धि का जिम्मा सँभाल रखा है। बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड ने 1951 के बाद से मौद्रिक नीति के संबंध में कई तरह के प्रयोग किये हैं जिनमें उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले ऋण के नियम निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में तरलता (नकदी की मात्रा) को समग्र रूप से देखना और मौद्रिक आधार को नियंत्रित करना शामिल है।

मौद्रिक नीति निर्धारित लक्ष्यों के हिसाब से चलती है। जैसे, कितनी मुद्रास्फीति होनी चाहिए, ब्याज दरों का कौन सा स्तर उचित होगा, बेरोज़गारी घटाने का समष्टिगत उद्देश्य कैसे पूरा किया जाए, सकल घरेलू उत्पाद कैसे बढ़ाया जाए, अर्थव्यवस्था की दीर्घकाल तक कैसे स्थिर रखा जाए, वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता के उपाय कैसे किये जाएँ, उत्पादन और दामों की स्थिरता कैसे कायम रखी जाए। मौद्रिकवाद के पैरोकार चाहते हैं कि सरकारी खर्च में कटौती की जाए और अर्थव्यवस्था पर लगे हुए नियंत्रण हटाये जाएँ। इनका दावा है कि अगर इतने महत्वपूर्ण लक्ष्यों को वेधने के लिए नीति के साथ अक्सर छेड़-छाड़ की जाएगी तो परिणामों की आकस्मिकता अस्थिरता पैदा कर सकती है। इसलिए ऐसे नियम बनाये जाने चाहिए कि सरकार न तो उधार ले सके और न ही बाज़ार में मनी की सप्लाई बढ़ा सके। इन अर्थशास्त्रियों को लगता है कि मौद्रिक नीति के संचालन में सरकार और राजनेताओं को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन, ऐसा होना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं होता। मोनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों की नियुक्तियों के ज़रिये सरकार इस नीति को प्रभावित करती रहती है। सरकार नीतिगत उद्देश्यों में तब्दीली करके और समष्टिगत नीतियों को अपने हिसाब से बदल कर स्वतंत्र मौद्रिक नीति के आग्रह को पनपने नहीं देती।

मौद्रिकवाद के मुख्य प्रणेता अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ़्रीडमैन और उनकी साथी अन्ना श्वार्ज़ हैं। इन दोनों ने अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा से संबंधित सिद्धांतों के आधार पर दीर्घावधि में होने वाली मनी सप्लाई और आर्थिक गतिविधियों के बीच संबंध का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले हैं। लेकिन, जब मौद्रिकवाद के सिद्धांत अमेरिकी, ब्रिटिश और अन्य युरोपीय देशों में लागू किये गये तो कई तरह की दिक्कतें सामने आयीं। धनापूर्ति (मनी सप्लाई) को परिभाषित करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। देखा गया कि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति का लक्ष्य बार-बार गड़बड़ा जाता है इसलिए हर बार नयी परिभाषा की ज़रूरत पड़ती है। धन के परिसंचरण और फैलाव की रक्रतार उतनी स्थिर और निरंतर साबित नहीं हुई जितना पहले समझा जा रहा था। राजकोषीय नीति का मतलब है सरकार अपने ख़जाने से क्या खर्च करना चाहती है और किस तरह के टैक्स लगा कर राजस्व हासिल करने की इच्छुक है। इसी नीति के साथ सरकार की ऋण नीति भी जुड़ी होती है ताकि अगर पर्याप्त राजस्व न प्राप्त होने की दशा में कर्ज़ उगाहे जा सकें। राजकोषीय नीति के आधार पर तय किया जाता है कि राष्ट्रीय आमदनी का कितना प्रतिशत कराधान से

उगाहा जाना चाहिए। इसी के साथ सवाल जुड़ा रहता है कि कम टैक्स लगा कर उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाए या ज्यादा टैक्स लगा कर लोकोपकारी परियोजनाएँ चलाई जाएँ जिससे आमदनी का समतामूलक पुनर्वितरण किया जा सके। राजकोषीय नीति का दूसरा सरोकार यह होता है कि टैक्स लगाये जाएँ तो किस प्रकार के। प्रत्यक्ष कर (जैसे आय कर) लगाये जाएँ या फिर बिक्री, माल और मूल्यवर्धन जैसे अप्रत्यक्ष कर लगाए जाएँ। अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव सभी लोगों की आमदनी पर पड़ता है। वह राजकोषीय नीति तटस्थ समझी जाती है जिसके कारण एक समूह के उपभोग दूसरे की अपेक्षा प्रभावित नहीं होता।

राजकोषीय नीति युद्ध और शांति के समय भिन्न-भिन्न होती है। युद्ध के समय सेना पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए उतने ही टैक्स लगाने के बजाय लोभ यह होता है कि ऋण लेकर काम चलाया जाए। दूसरी तरफ़ अगर सरकार के ऊपर काफी कर्ज लदा हुआ है तो शांतिकाल में वह लोकोपकारी योजनाएँ चलाने के लिए राजस्व की जुगाड़ करने के बजाय कर्ज उतारने में धन खर्च करती नज़र आयेगी। राजकोषीय नीति के जरिये बुद्धिमान सरकारें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की भूमिका निभा सकती हैं। मसलन, अगर मंदी का दौर चल रहा है तो सरकार कम टैक्स लगाने और अधिक खर्च करने का फैसला ले सकती है। तेज़ी के दौर में ज्यादा टैक्स लगाये जा सकते हैं और खर्चा कम करके सार्वजनिक वित्त यानी सरकारी खज़ाने की हालत सुधारी जा सकती है।

राजकोषीय संघवाद इसी नीति का अंग है। इसके तहत राष्ट्रीय, प्रादेशिक और शहर के स्तर पर अलग-अलग कराधान और व्यय संबंधी नीतियाँ अपनायी जाती हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि और मुद्रास्फीति

भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1970 के दशक में 3.5: से बढ़कर 1980 के दशक में 5.5: हो गई। वृद्धि में इस वृद्धि को मांग और आपूर्ति-पक्ष दोनों कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन यह सुझाव दिया गया है कि श्कीनेसियन विस्तार, या उच्च सरकारी खर्च और बड़े राजकोषीय घाटे के कारण कुल मांग में वृद्धि, मुख्य रूप से विकास दर (जोशी और लिटिल 2018) को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थी। 1980 के दशक की शुरुआत में सार्वजनिक निवेश तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन दशक के उत्तरार्ध में यह धीमा हो गया और सरकारी उपभोग व्यय बहुत तेज़ गति से बढ़ा। राजस्व घाटा बढ़ गया, यह दर्शाता है कि सरकारी खपत को उधार लेकर वित्तपोषित किया जा रहा था, जिसमें ब्याज और पुनर्भुगतान प्रतिबद्धताएं शामिल थीं।

कम से कम अल्पावधि में उत्पादन वृद्धि को बढ़ाने में विस्तारवादी राजकोषीय नीतियों की सफलता को आंशिक रूप से पूर्ववर्ती वर्षों में उत्पादक क्षमता के कम उपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 1980 के दशक के अंत तक, जब उत्पादन प्रवृत्ति के स्तर से ऊपर था, एक राजकोषीय नीति प्रणाली में अतिरिक्त मांग पैदा करने वाली विस्तारवादी बनी रही (जोशी और लिटिल 2019)।

वित्तीय क्षेत्र के सुधार में प्राथमिक रूप से वैधानिक तरलता अनुपात में कमी और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को रियायती ऋण का युक्तिकरण, ब्याज नियंत्रण में छूट और पूंजी बाजार में फर्मों की पहुंच पर प्रतिबंध और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अधिक स्वायत्तता शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र के

उद्यमों के मामले में प्रमुख सुधार में बाहरी और घरेलू प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा और बजट और बैंक संसाधनों तक तरजीही पहुंच जैसे विशेषाधिकारों को समाप्त करना शामिल था। हालांकि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में घाटे में चल रही फर्मों को बंद करने या पुनर्गठन के लिए एक प्रभावी निकास नीति से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, किए गए सुधार काफी हद तक कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

मौद्रिक नीति और विकास

पिछले डेढ़ दशकों में भारतीय विकास प्रक्रिया की एक उल्लेखनीय विशेषता इसकी स्थिरता रही है। यह पूर्व-सुधार अवधि के दौरान, यानी नब्बे के दशक से पहले की तुलना में सुधार के बाद की अवधि के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि की भिन्नता के काफी कम गुणांक से स्पष्ट है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत की वृद्धि घरेलू खपत से प्रेरित है, जो कुल मांग में औसतन लगभग दो-तिहाई का योगदान करती है, जबकि निवेश और निर्यात मांग में भी तेजी आ रही है। चूंकि खपत मांग का कम अस्थिर घटक है, इसने जीडीपी की अस्थिरता को कम करने में भी योगदान दिया है।

1950 के दशक के दौरान 1.7: के वार्षिक औसत से 1960 के दशक के दौरान 6.4: और 1970 के दशक में आगे 9.0: तक मुद्रास्फीति की दर में तेजी से वृद्धि हुई, जो 1980 के दशक में मामूली रूप से 8.0: तक कम हो गई। भारत ने आम तौर पर भगोड़ा मुद्रास्फीति का अनुभव नहीं किया था। दूसरी ओर, भिन्नता के गुणांक द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति दर में अस्थिरता, जो 1950 के दशक में 4.4 पर काफी अधिक थी, बाद के दशकों में 0.4–1.0 के एक संकीर्ण बैंड में चली गई, जिससे मुद्रास्फीति-जोखिम कम हो गया। अधिमूल्य। 1970 के दशक के बाद से मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि ने मुद्रा आपूर्ति वृद्धि में तेज वृद्धि के प्रभाव को दर्शाया और कच्चे तेल की कीमतों और फसल की विफलता से आंशिक रूप से आपूर्ति झटके। आंशिक रूप से बढ़ते राजकोषीय असंतुलन से उत्पन्न मांग दबावों ने भी 1980 के दशक में मुद्रास्फीति के दबावों में योगदान दिया। 1990 के दशक की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति के परिणाम में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जो बेहतर मौद्रिक-राजकोषीय इंटरफेस को दर्शाता है।

मुद्रास्फीति मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से आर्थिक विकास को बाधित कर सकती है

जो अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति की दी गई दर से पूरी तरह से समायोजित नहीं होती हैं, वे आमतौर पर मुद्रास्फीति के कारण सापेक्ष मूल्य विकृतियों से ग्रस्त होती हैं। नाममात्र ब्याज दरों को अक्सर नियंत्रित किया जाता है, और इसलिए वास्तविक ब्याज दरें नकारात्मक और अस्थिर हो जाती हैं, बचत को हतोत्साहित करती हैं। विनिमय दरों का मूल्यहास मुद्रास्फीति से पिछड़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक मूल्यवृद्धि और विनिमय दरों में परिवर्तनशीलता होती है।

वास्तविक कर संग्रह मुद्रास्फीति के साथ नहीं रहता है, क्योंकि संग्रह पिछले वर्ष (तंजी प्रभाव) की मामूली आय पर आधारित होते हैं और सार्वजनिक उपयोगिता की कीमतें मुद्रास्फीति के अनुरूप

नहीं बढ़ाई जाती हैं। दोनों कारणों से, मुद्रास्फीति से राजकोषीय समस्या तेज हो जाती है, और सार्वजनिक बचत कम हो सकती है। इससे सार्वजनिक निवेश पर विपरीत असर पड़ सकता है।

उच्च मुद्रास्फीति अस्थिर है। मुद्रास्फीति की भविष्य की दरों के बारे में अनिश्चितता है, जो निवेश की दक्षता को कम करती है और संभावित निवेशकों को हतोत्साहित करती है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. बिहार की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और सरकारी खर्च के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए
2. भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि और मुद्रास्फीति का अध्ययन करने के लिए

अनुसंधान क्रियाविधि

इस शोध पत्र में हम बिहार की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और सरकारी खर्च के बीच संबंध बता रहे हैं। इसलिए इस अध्ययन की अनुसंधान क्रिया विधि भारत में मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास पर निर्भर करती है।

डेटा विश्लेषण

बिहार बजट विश्लेषण

2021–22

बिहार के वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 22 फरवरी, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया। कोविड-19 के असर की वजह से वर्ष 2020–21 अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त के लिहाज से स्टैंडर्ड वर्ष नहीं था। इस नोट में 2021–22 के बजट अनुमानों की तुलना 2019–20 के वास्तविक आंकड़ों से की गई है (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर या सीएजीआर के संदर्भ में)। अनुलग्नक में 2020–21 के संशोधित अनुमानों और 2021–22 के बजट अनुमानों के बीच तुलना की गई है।

बजट के मुख्य अंश

- 2021–22 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा मूल्यों पर) 7,57,026 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें 2019–20 की तुलना में 11: की वार्षिक वृद्धि है। संशोधित अनुमानों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 में जीएसडीपी में 4.7: की वृद्धि अनुमानित है (बजट अनुमान 11.1: थे)।
- 2021–22 के लिए कुल व्यय 2,18,303 करोड़ रुपए अनुमानित है जिसमें 2019–20 की तुलना में 23: की वार्षिक वृद्धि है। संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2020–21 में कुल व्यय, बजट अनुमान से 6: अधिक होने की उम्मीद है (13,697 करोड़ रुपए की वृद्धि)।

- 2021–22 के लिए कुल प्राप्तियां (उधारियों के बिना) 1,86,697 करोड़ रुपए अनुमानित हैं जिसमें 2019–20 की तुलना में 23: की वार्षिक वृद्धि है। 2020–21 में कुल प्राप्तियां बजट अनुमान से 9,684 करोड़ रुपए कम रहने का अनुमान है (5: की गिरावट)।
- 2021–22 के लिए राजस्व अधिशेष 9,196 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जोकि जीएसडीपी का 1.21: है। 2020–21 में (संशोधित अनुमान) राज्य को 5,187 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान है (जीएसडीपी का 0.8:)।
- 2021–22 में राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़ रुपए पर लक्षित है (जीएसडीपी का 2.97:)। संशोधित अनुमान के अनुसार, 2020–21 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 6.77: अनुमानित है जो जीएसडीपी के 2.97: के बजट अनुमान से काफी अधिक है।

नीतिगत विशिष्टताएं

- सात निश्चय योजना-2रू राज्य 2021–22 में सात निश्चय योजना-2 को लागू करेगा। 2021–22 में इस कार्यक्रम के लिए 4,671 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
- सात निश्चय-2 के अंतर्गत मुख्य योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैंरू (प) पॉलिटैक्निक्स और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना, (पप) हर जिले में मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर और हर डिविजन में टूल रूम का स्थापना, (पपप) नए व्यवसाय शुरू करने के लिए युवाओं और महिलाओं को सबसिडियुक्त ब्याज दरों पर पांच लाख रुपए तक का अनुदान और पांच लाख रुपए तक के लोन, (पअ) बालिकाओं को नकद प्रोत्साहन: सीनियर सेकेंडरी पूरी करने पर 25,000 रुपए और ग्रैजुएशन पूरी करने पर 50,000 रुपए, (अ) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन, पैथोलॉजी, डायबिटीज़-ब्लड प्रेशर इत्यादि की स्क्रीनिंग का प्रावधान, और (अप) शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों और भूमिहीन गरीबों के लिए आवास और वृद्धों के लिए सभी शहरों में शेल्टर होम्स।

शिक्षा: डिजिटल बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा छह और उससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को 2021–22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण मिलेगा। राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल दाखिला अनुपात को बढ़ाकर 50: करने के लिए कदम उठाएगी।

बिहार की अर्थव्यवस्था

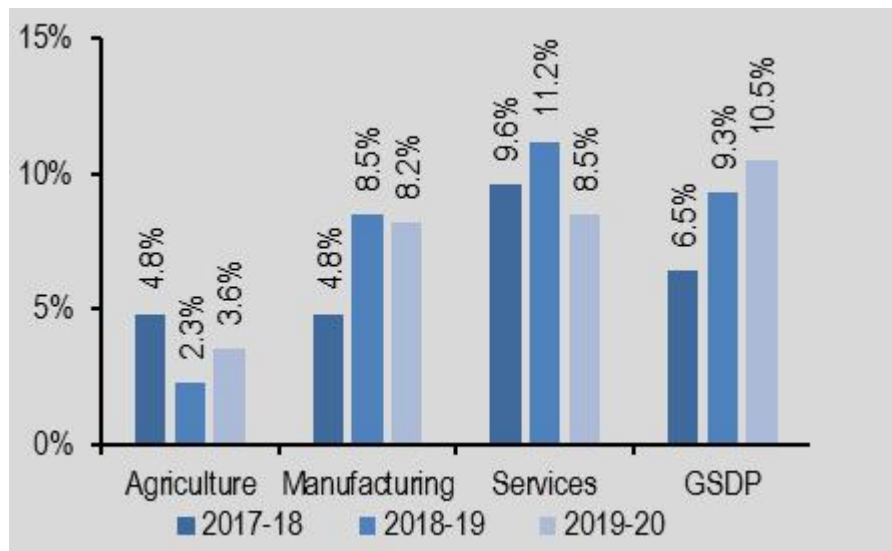
जीएसडीपीरू 2019–20 में बिहार की जीएसडीपी (स्थिर मूल्यों पर) की वृद्धि दर 10.5: थी, जोकि 2018–19 की वृद्धि दर से अधिक है (9.3:)।

क्षेत्ररू 2019–20 में अर्थव्यवस्था में कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों ने क्रमशः 20:, 20: और 60: का योगदान दिया।

प्रति व्यक्ति जीएसडीपीरू 2019–20 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (स्थिर मूल्यों पर) 34,413 रुपए थी जोकि 2018–19 के मुकाबले 8.8: अधिक है।

बेरोजगारीरू पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वे (जुलाई 2018– जून 2019) के अनुसार, सभी आयु वर्गों में राज्य की बेरोजगारी दर 10.2: थी, जो देश की दर (5.8:) से काफी ज्यादा है।

रेखाचित्र 1: बिहार में स्थिर मूल्यों पर (2011–12) जीएसडीपी और विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि



नोटरू आंकड़े स्थिर मूल्यों (2011–12) पर आधारित हैं जिसका यह अर्थ है कि वृद्धि दर को मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित किया गया है।

2021–22 के लिए बजट अनुमान

- 2021–22 में 2,18,303 करोड़ रुपए के कुल व्यय का अनुमान है। इसमें 2019–20 की तुलना में 23: की वार्षिक वृद्धि है। इस व्यय को 1,86,697 करोड़ रुपए की प्राप्तियों (उधारियों के अतिरिक्त) और 31,805 करोड़ रुपए की उधारियों के जरिए पूरा किया जाना प्रस्तावित है। 2019–20 की तुलना में 2021–22 में कुल प्राप्तियों (उधारियों के अतिरिक्त) में 23: की वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है।
- 2021–22 के लिए राज्य ने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी का 2.97: अनुमानित किया है। यह 2021–22 में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के राजकोषीय घाटे की 4: की अनुमत सीमा से कम है। आर्थिक बहाली को सहयोग देने के लिए व्यय बढ़ाने हेतु एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत राज्यों को 3: की सामान्य सीमा से अधिक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी गई है।

2021-22 में राज्य ने 9,196 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया है जोकि 2019-20 में राजस्व अधिशेष से काफी अधिक है (263: की वार्षिक वृद्धि)।

- 2020-21 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, प्राप्तियों (उधारियों के अतिरिक्त) के बजट अनुमान से 5: कम होने की उम्मीद है जबकि कुल व्यय के बजटीय अनुमानों की तुलना में 6: अधिक होने का अनुमान है। पिछले पांच वर्षों में राज्य में राजस्व अधिशेष हुआ है लेकिन 2020-21 में यह अनुमान है कि 5,187 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होगा (जीएसडीपी का 0.80:)। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 6.77: होना अनुमानित है (संशोधित अनुमानों के अनुसार) जोकि 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के राजकोषीय घाटे की 5: की अनुमत सीमा से अधिक है।

तालिका 1: बजट 2021-22 के मुख्य आंकड़े (करोड़ रुपए में)

मद	2019-20 वास्तविक	2020-21 बजटीय	2020-21 संशोधित	बअ 2020-21 से संअ 2020-21 में परिवर्तन का %	2021-22 बजटीय	वार्षिक परिवर्तन (2019-20 से बअ 2021-22)
कुल व्यय	1,43,614	2,11,761	2,25,458	6%	2,18,303	23%
क. प्राप्तियां (उधारियों के बिना)	1,24,263	1,84,352	1,74,668	-5%	1,86,697	23%
ख. उधारियां	29,145	27,609	37,629	36%	31,805	4%
कुल प्राप्तियां (ए+बी)	1,53,408	2,11,961	2,12,297	0%	2,18,503	19%
राजस्व संतुलन	699	19,173	5,187	-127%	9,196	263%
जीएसडीपी का %	0.11%	2.80%	-0.80%		1.21%	
राजकोषीय घाटा	12,241	20,374	43,737	115%	22,511	36%
जीएसडीपी का %	1.98%	2.97%	6.77%		2.97%	
प्राथमिक घाटा	1,250	7,449	30,786	313%	7,993	153%
जीएसडीपी का %	0.20%	1.09%	4.76%		1.06%	

नोट्स: बअ— बजट अनुमान; संअ— संशोधित अनुमान। नेगेटिव राजस्व संतुलन घाटे को दर्शाता है।

2021-22 में व्यय

- 2021-22 में पूंजीगत व्यय 41,231 करोड़ रुपए प्रस्तावित है जिसमें 2019-20 की तुलना में 43: की वार्षिक वृद्धि है। पूंजीगत व्यय में ऐसे व्यय शामिल हैं, जोकि राज्य की परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करते हैं, जैसे (प) पूंजीगत परिव्यय यानी ऐसा व्यय जोकि परिसंपत्तियों का सृजन (जैसे पुल और अस्पताल) करता है और (पप) राज्य सरकार द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान और ऋण देना। 2021-22 में पूंजीगत परिव्यय (30,788 करोड़ रुपए) में 2019-20 की तुलना में 58: की वार्षिक वृद्धि अनुमानित है।

- 2021-22 के लिए 1,77,071 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय प्रस्तावित है जिसमें 2019-20 की तुलना में 20: की वृद्धि है। इसमें वेतन का भुगतान, ब्याज और सब्सिडी शामिल हैं। 2020-21 में राजस्व व्यय के बजट अनुमान से 9: अधिक होने का अनुमान है।
- संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2020-21 में जबकि राजस्व व्यय बजट अनुमान से 9: अधिक अनुमानित है, पूंजीगत परिव्यय के 3: कम होने का अनुमान है।

तालिका 2रू बजट 2021-22 में व्यय (करोड़ रुपए में)

मद	2019-20 वास्तविक	2020-21 बजटीय	2020-21 संशोधित	बअ 2020-21 से संअ 2020-21 में परिवर्तन का %	2021-22 बजटीय	वार्षिक परिवर्तन (2019-20 से बअ 2021-22)
पूंजीगत व्यय	20,080	47,010	46,032	-2%	41,231	43%
जिसमें पूंजीगत परिव्यय	12,304	38,745	37,748	-3%	30,788	58%
राजस्व व्यय	1,23,534	1,64,751	1,79,426	9%	1,77,071	20%
कुल व्यय	1,43,614	2,11,761	2,25,458	6%	2,18,303	23%
क. ऋण पुनर्भुगतान	7,110	7,035	7,053	0.3%	9,094	13%
ख. ब्याज भुगतान	10,991	12,925	12,951	0.2%	14,517	15%
ऋण चुकोती (क+ख)	18,101	19,960	20,004	0.2%	23,612	14%

नोट्सरू बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। पूंजीगत परिव्यय का अर्थ ऐसा व्यय है जिससे परिसंपत्तियों का सृजन होता है।

निष्कर्ष

यह अध्ययन साहित्य में हाल के घटनाक्रमों से मुद्रास्फीति और विकास के बीच संबंधों और विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रदान किए गए स्पष्ट विरोधाभासी साक्ष्य से प्रेरित है। इस पत्र में, सह-एकीकरण और त्रुटि सुधार मॉडल ने वार्षिक डेटा का उपयोग करके भारत में मुद्रास्फीति-आर्थिक विकास संबंधों की दीर्घकालिक और अल्पकालिक गतिशीलता की अनुभवजन्य जांच की है। मुख्य उद्देश्य यह जांचना था कि क्या आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति के बीच संबंध मौजूद है और यदि हां, तो इसकी प्रकृति। इस अभ्यास में पाया गया दिलचस्प परिणाम यह है कि मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास नकारात्मक रूप से संबंधित हैं। दूसरा, विकास दर में परिवर्तन के प्रति मुद्रास्फीति की संवेदनशीलता, मुद्रास्फीति दरों में परिवर्तन के प्रति विकास की संवेदनशीलता से अधिक है। इन निष्कर्षों के महत्वपूर्ण नीतिगत निहितार्थ हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

- [1] ए. पीकॉक और जी.के. शॉ (1971), द इकॉनॉमिक थियरी ऑफ़ फ़िश्कल पॉलिसी, जॉर्ज एलेन और अनविन, लंदन.

- [2] पी. बोफिंगर (2001), मोनेटरी पॉलिसी रू गोल्स, इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रैटजीज़ एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ऑक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफ़र्ड.
- [3] एम. ब्लॉग वगैरह (1995), द क्वांटिटी थियरी ऑफ़ मनी फ़ॉर्म लॉक टू कीस एंड फ़्रीडमैन, एडवर्ड एलगर, एल्डरशॉट.
- [4] मिल्टन फ़्रीडमैन (1968), 'रोल ऑफ़ मोनेटरी पॉलिसी', अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्यू, 58.
- [5] हेने, पी. टी. बोटके, पी. जे., प्रिकितको, डी. एल.(2002)रू द इकोनोमिक वे ऑफ़ थिंकिंग (10 वां संस्करण). प्रेंटिस हॉल.
- [6] एटेसोग्लू, एच.एस., 1998. इन्फ्लेशन एंड रियल इनकम, जर्नल ऑफ़ पोस्ट केनेसियन इकोनॉमिक्स 20, पी। 487.
- [7] बैरो, आर.जे., 1995. मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास, बैंक ऑफ़ इंग्लैंड क्वार्टरली बुलेटिन, पी। 166.
- [8] ब्लश, टी., 1978. डायनेमिक लीनियर मॉडल्स में ऑटोसहसंबंध के लिए टेस्टिंग, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक पेपर्स 17, पी. 334.
- [9] ब्लूनो, एम एंड ईस्टरली, डब्ल्यू., 1998. इन्फ्लेशन क्राइसिस एंड लॉन्ग रन ग्रोथ, जर्नल ऑफ़ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स 41, 3.
- [10] देवराजन, एस., स्वरूप, वी., जू, एच., 1996। सार्वजनिक व्यय और आर्थिक विकास की संरचना, मौद्रिक अर्थशास्त्र के जर्नल 37, 313।
- [11] एरिक्सन, एन.आर., आयरन्स, जे.एस., ट्राईटन, आर.डब्ल्यू., 2001. लॉन्ग रन में आउटपुट एंड इन्फ्लेशन, जर्नल ऑफ़ एप्लाइड
- [12] फिशर, एस., 1993. ग्रोथ में मैक्रो-इकोनॉमिक फैक्ट्स की भूमिका, जर्नल ऑफ़ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स 32, पी। 482.